-I (I)
Paper-I
Date: 04/04/2…

लोककल्याणकारी राज्य

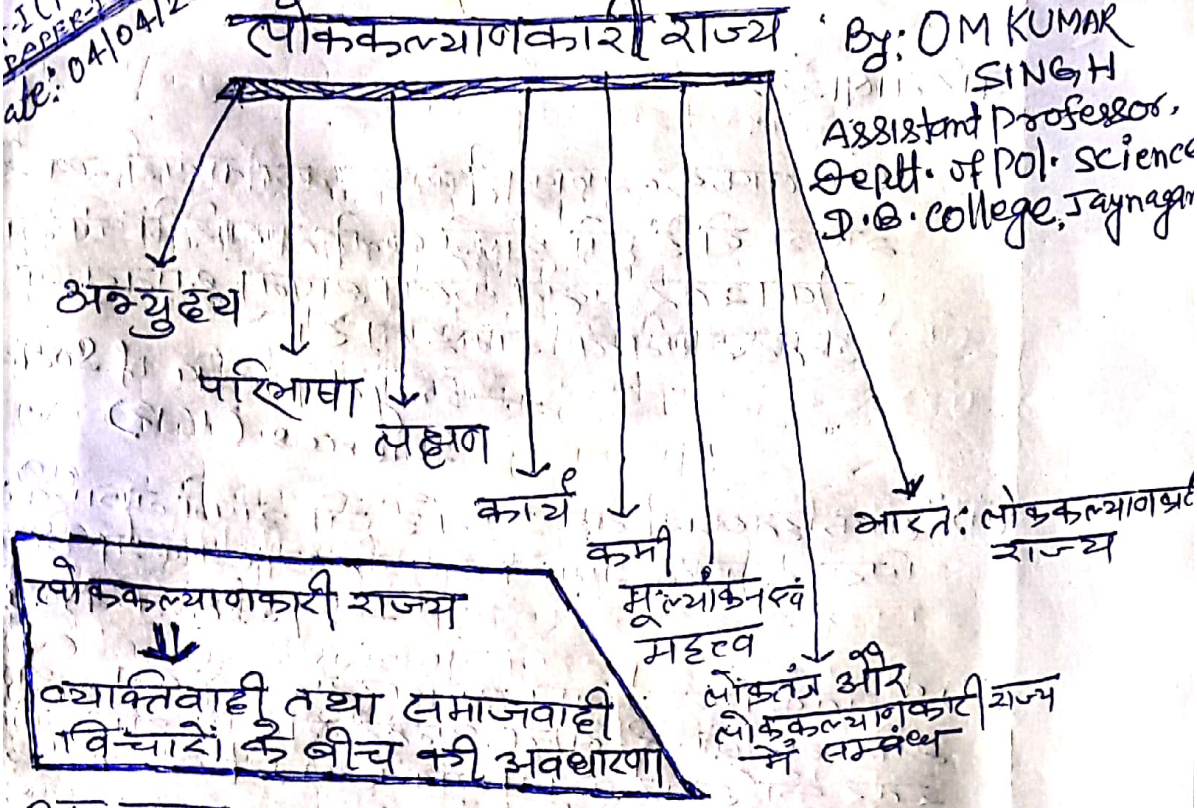

By: OM KUMAR SINGH
Assistant Professor,
Deptt. of Pol. Science
D.B. College, Jaynagar

- अभ्युदय
- परिभाषा
- लक्षण
- कार्य
- कमी
- मूल्यांकन एवं महत्व
- लोकतंत्र और लोककल्याणकारी राज्य में सम्बन्ध
- भारत: लोककल्याणकारी राज्य

लोककल्याणकारी राज्य
⇓
व्यक्तिवादी तथा समाजवादी विचारों के बीच की अवधारणा

अभ्युदय:

आधुनिक उदारवादी सिद्धांत से ही 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई। टी० एच० ग्रीन को इस अवधारणा का अग्रदूत माना जा सकता है।

'कल्याणकारी राज्य' शब्द का प्रयोग पहली बार आर्कबिशप टैम्पिल ने अपनी कृति 'Citizen and Churchman' में अधिनायकों के 'सत्तावादी राज्य' शब्द के विरोध में किया।

ब्रिटेन को पहला लोककल्याणकारी राज्य माना जाता है; क्योंकि वहाँ की एटली सरकार के द्वारा पाँच बड़ी बुराइयों – बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रयाभाव के समाप्ति में राज्य की सकारात्मक भूमिका सम्बन्धी लॉर्ड विलियम बेवरिज की 1943 की रिपोर्ट लागू की गई। वैसे लोककल्याणकारी राज्य का विचार नया नहीं है। भारत में प्राचीन काल से रामराज्य की धारणा प्रचलित है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। महाभारत, पाराशर की स्मृतियाँ तथा मार्कण्डेय, मनु और याज्ञवल्क्य, आदि की विचारधारा में लोककल्याण की बात स्पष्टया देखी जा सकती है। वेदव्यास ने महाभारत में कहा है कि "जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वह नरक का भागी होता है।" इसी तरह की धारणा यूनान में भी प्रचलित थी। प्लेटो और अरस्तु के विचार भी इसी तरह के रहे हैं। टामस पेन, थामस जेफरसन, काण्ट, ग्रीन और बेंथम की विचारधाराओं में राज्य का कार्य लोक कल्याण होना चाहिए, स्पष्ट होता है।

Scanned with CamScanner

(2)

परिभाषाएँ :

(i) लोककल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवनस्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है।"
— Encyclopaedia of Social Sciences (1948)

(ii) "लोकहितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है।"
— टी० डब्ल्यू० केण्ट

(iii) "सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अन्तर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोकहितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं।"
— जवाहरलाल नेहरू

(iv) "कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है।"
— डॉ० अब्राहम

(v) "लोककल्याणकारी राज्य का कार्य एक ऐसे पुल का निर्माण करना है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन की पतित अवस्था से निकलकर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके, जो उत्थानकारी और उद्देश्यपूर्ण है। इस राज्य का यथार्थ उद्देश्य नागरिक द्वारा स्वतंत्रता के उपभोग को सम्भव बनाना है।"
— न्यायमूर्ति छागला

(vi) "कल्याणकारी राज्य दो अतिथियों में एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है तो दूसरी तरफ अनियन्त्रित व्यक्तिवाद।"
— होब्सन

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करते हुए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। यह अपने नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Scanned with CamScanner

क्रमशः :- लक्षण/विशेषताएँ :

(i) लोककल्याण का लक्ष्य ।
(ii) आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था ।
(iii) अधिकतम समानता की स्थापना करना ।
(iv) राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि ।
(v) सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था ।
(vi) सभी व्यक्तियों के रोजगार ।
(vii) न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी ।
(viii) राजनीति व्यवस्था उचित प्रकार से करना ।
(ix) नागरिक स्वतंत्रताएँ ।
(x) गरीबी उन्मूलन ।
(xi) समानता ।
(xii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना ।

कार्य :

लोककल्याणकारी राज्य के कार्य काफी विस्तृत हैं । इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) आन्तरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना ।
(ii) कृषि, उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास करना ।
(iii) शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का उचित प्रबंध करना ।
(iv) जनमानस के जीवन-स्तर को ऊपर उठाना ।
(v) सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करना ।
(vi) व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के सम्बंधों की व्यवस्था करना ।
(vii) नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उचित कदम उठाना ।
(viii) नागरिकों को आमोद-प्रमोद की सुविधाएँ उपलब्ध करना ।
(ix) नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करना ।
(x) न्याय व्यवस्था करना ।
(xi) उचित मुद्रा प्रबंधन ।
(xii) कर संग्रह ।

P.T.O.

लोककल्याणकारी राज्य की कमियाँ :-

(i) अत्यधिक खर्चीला ;

(ii) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन ;

(iii) नौकरशाही का भय ;

(iv) ऐच्छिक समुदाय पर आघात ;

मूल्यांकन एवं महत्त्व :

वास्तव में लोककल्याणकारी राज्य की उपर्युक्त कमियाँ इस राज्य की नहीं हैं, वरन् मानवीय जीवन की है। इसमें सुधार लाकर एवं दूर कर लोककल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। व्यवहार में लोककल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति को विश्व में अनेक [illegible] राज्यों के द्वारा किसी-न-किसी रूप में अपना लिया गया है, जो इसके महत्त्व को स्वतः स्थापित करता है।

लोकतंत्र और लोककल्याणकारी राज्य में सम्बन्ध :

कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र में गहरा सम्बन्ध है। लोककल्याण की प्रवृत्ति ने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की। विश्व के अनेक देशों ने इसे अपनाकर कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान किया है। हालाँकि वर्तमान में भी कई देश आर्थिक विषमता आदि कई संकटों से जूझ रहे हैं। इन समस्यों का समाधान लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपनाकर किया जा सकता है। लोकतंत्र और लोककल्याणकारी राज्य एक-दूसरे के पूरक हैं और वर्तमान परिस्थिति में लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लोककल्याण की प्रवृत्ति को अपनाया जाना नितान्त जरूरी है।

भारत : लोककल्याणकारी राज्य :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर लोककल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया।

x——x——x——x

By: OM KUMAR Singh
Assistant Professor

संभावित प्रश्न : लोककल्याणकारी राज्य से क्या समझते हैं। इसके लक्षणों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।